lakh family type and 450 community, institutional and night-soil based biogas plants fixed for the entire Eight Five Year Plan period (1992-97), already over 7.85 lakh family type and 877 community, institutional and night-soil based biogas plants have been set up in different States and Union Territories (UTs) during the first four years i.e. (1992-96). A target of setting upp of 1.80 lakh family type and 250 community, institutional and night-soil based biogas plans has been proposed for the current financial year 1996-97.

(b) to (d) While several States/UTs have been constantly achieving, rather exceeding their targets only some States/UTs have slow progress. During 1995-96, the States of Assam, Bihar, Gujarat, Goa, Jammu & Kashmir, Karnataka, Kerala, Meghalaya, Nagaland, Punjab, Tamil Nadu and West Bengal and U.T. of Chandigarh and Pondicherry could not achieve their targets for setting up of family type biogas plants due to reasons varying from State to State, such as lach of additional financial and organizational support under State Plan Sector; inadequate involvement of non-governmental organizations and entrepreneurs; difficulty in getting loans from banks, shortage of trained masons and inadequate maintenance servicing facilities. These States/UTs are also taking steps to improve the progress.

जल की आपूर्ति हेतु राष्ट्रीय नीति

455. **श्री मोहिन्दर सिंह कल्याण:** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेषकर देश के पेय जल के अभाव की समस्या वाले राज्यों/क्षेत्रों में जलपूर्ति हेतु कोई राष्ट्रीय नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार सभी नागरिकों हेतु पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय कर रही है और पेयजल की समस्या का कब तक समाधान कर दिये जाने की संभावना है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री चन्द्र देव प्रसाद वर्मा): (क) केन्द्र सरकार ने राज्यों के परामर्श से पेयजल की कमी की समस्या से प्रभावित कवर न की गई और आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति के लिए नीति तैयार की है।

(ख) 1.4.96 तक, विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 75,783 कवर न की गई और 3,31,646 आंशिक रूप से कवर की गई बसावटें थीं। सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से बाकी बची कवर न की गई और आंशिक रूप से कवर की गई बसावटों को कवर करने और निधियों की कुल मांग, राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत संसाधनों की उपलब्धता और केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलापूर्तिकार्यक्रम के अंतर्गत आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने के लिए ठोस कार्य योजनाएं तैयार करने का अनुरोध किया गया है। 1997-98 तक सभी कवर न की गई और आंशिक रूप से कवर की गई (प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 10 लीटर से कम पानी प्राप्त करने वाली) बसावटों को पेयजल उपलब्ध करा दिए जाने की संभावना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) शेष आंशिक रूप से कवर की गई सभी बसावटों को सन 2000 ई० तक स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा दिया जाएगा। पेयजल की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए किए गए उपायों में पहले से ही की गई आवश्यक आयोजना, योजनाओं को बनाना, राज्यों द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम तथा त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी योजनाओं को तकनीकी और प्रशासनिक अनुमोदन तथा फील्ड में कार्यान्वयन, प्रगति की निगरानी तथा राज्यों के साथ बैठकों में समय समय पर समीक्षा करना शामिल है। केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा आवश्यक निधियां जुटायी जायेंगी।

Survey to Identify Barren Land in Karnataka

456. **SHRI JANARDHANA POOJARY:** Will the Minister of RURAL AREAS AND EMPLOYMENT be pleased to state:

(a) whether the Government have conducted any survey to identify barren land in Karnataka; if so, the details thereof;

(b) whether any research has been conducted to make such land fertile by scientific methods; if so, the details thereof; and

(c) whether any barren land has been made fertile during the last one year and so far in 1996; if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS AND EMPLOYMENT (SHRI CHANDRADEO PRASAD VERMA): (a) No survey has been conducted for the identification of barren land in Karnataka. However, department of Wastelands Development has commissioned National Wastelands Identification Project with the collaboration of National Remote Sensing Agency. Under this project, districts having more than 5% of geographical area as wastelands have been mapped. The districts covered are Bangalore, Belgaum, Bijapur, Bidar, Bellary, Chitadurga, Chikmagalur, Gulbarga, Hassan, Kolar, Mandya, Raichur, Shimoga and Tumkur, having a total of 1.71 million ha. of wastelands, including barren land in the State.

(b) and (c) The Department of Wastelands Development is implementing the following schemes for Development of wastelands. The area treated in Karnataka during 1995-96 is indicated against each scheme:

Scheme	Area covered during 1995-96 (in ha.)
1. Integrated Wastelands Development Projects	2675
2. Technology Development Extension & Training	100
3. Grants-in-Aid to Voluntry Agencies.	330

पन बिजली परियोजनाओं में हिमाचल प्रदेश का हिस्सा

457. **श्री महेश्वर सिंह:** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश सरकार हिमाचल प्रदेश में बनाई गई पन बिजली परियोजनाओं में पंजाब और हरियाणा सरकारों से अपना हिस्सा प्राप्त करने हेतु केन्द्रीय सरकार से बार-बार अनुरोध करती रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस क्षेत्र में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने हिमाचल प्रदेश सरकार को अब तक कितनी सहायता उपलब्ध कराई है?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० एस० वेणुगोपालाचारी): (क) और (ख) जी, हां हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश में स्थित भाखड़ा-नांगल और ब्यास परियोजना के चालू होने की तिथि से 7.19% की बढ़ी हुई हकदारी और 12% निःशुल्क विद्युत के हिस्से के लिए अपना दावा करती रही है। हिमाचल प्रदेश की राज्य सरकार ने मामले में निर्णय हेतु प्रार्थना करते हुए उच्चतम न्यायालय में जून, 1996 में एक याचिका भी दायर की है।

(ग) राष्ट्रीय जल विद्युत शक्ति निगम की केन्द्रीय क्षेत्र वाली परियोजनाओं यथा; बैरा स्यूल (198 मे०वा०) और चमेरा चरण-1 (540 मे०वा०) से 12% निःशुल्क विद्युत हिमाचल प्रदेश राज्य को प्रदान की गयी है। राज्य को उसकी विद्युत ऊर्जा और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अंतःराज्यीय अंतरण की सुविधा भी प्रदान की जाती है। अप्रैल-मई, 1996 के दौरान हिमाचल प्रदेश को पश्चिमी क्षेत्र के अतिरिक्त पंजाब और उत्तर प्रदेश से 85.1 मि०यू० विद्युत प्रदान की गयी है।

Kayamkulam Thermal Power Project

458. SHRI M.A. BABY: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) the details of the present stage of the Kayamkulam Thermal Power Project;

(b) the details regarding the financial tie up for the above project;

(c) the expected date of the award of the main plant contract; and

(d) the details of the time schedule of commissioning of the entire project?